PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Hindustan, Delhi
Tue, 23 May 2017, Page 15
Width: 51.02 cms, Height: 46.04 cms, a3r, Ref: 42.2017-05-23.181

नोटबंदी : 23 हजार करोड़ के कालेधन का खुलासा

मोदी सरकार ने आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी का साहसिक कदम उठाया। इससे करीब 23 हजार करोड़ रुपये का कालाधन सामने आया। अगले तीन दिन हिन्दुस्तान पड़ताल करेगा कि सरकार ने पिछले तीन साल में कौन से बड़े फैसले किए, उनका क्या असर हुआ और क्या सवाल बाकी रह गए हैं।

7.1% रही विकास दर अक्तूबर-दिसंबर 2016 की तिमाही में

91 लाख आयकरदाता बढ़े नोटबंदी के बड़े फैसले के बाद

4% तक छूट का ऐलान आवास ऋण में 31 दिसंबर 2016 को

30 हजार का आंकड़ा पार कर गया सेंसेक्स 5 अप्रैल 2017 को

नई दिल्ली | पीयूष पांडे

केंद्र सरकार ने नोटबंदी और कर ढांचे में सुधार से जुड़ी जीएसटी प्रणाली के जरिये भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार किया। तीन सालों में आर्थिक विकास की रफ्तार 7% के करीब बनी रही है। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई काबू में रखना और विकास दर को 8-9 प्रतिशत पर ले जाने का लक्ष्य सरकार के शेष कार्यकाल की अहम चुनौती होगी।

सरकार का मानना है एक देश-एक कर वाले जीएसटी से कर चोरी रुकेगी और कई आवश्यक वस्तुओं के दाम घटेंगे। सरल कर ढांचे से उत्पीड़न और कानूनी केस भी कम होंगे। मानसून और वैश्विक ढांचे को देखते हुए वित्तीय वर्ष की अवधि भी 1 अप्रैल से 31 मार्च की जगह 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक करने की तैयारी दिखाती है कि सरकार आर्थिक सुधारों को लेकर कितनी चिंतित है।

केंद्र ने आर्थिक योजनाएं लागू करने में अहम सरकारी बैंकों का ढांचा मजबूत करने और उनकी स्वायत्तता-जवाबदेही के लिए भी कदम उठाए हैं। स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों का विलय बड़ा फैसला रहा। बैंकों के डूबते कर्ज से निपटने की दिशा में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव का अध्यादेश आया ताकि रिजर्व बैंक ज्यादा स्वायत्तता से निर्णय ले सके। रेल बजट का आम बजट में विलय के साथ बजट को 1 फरवरी को पेश करने का फैसला किया गया, ताकि बजटीय औपचारिकताएं जल्द पूरी हो सकें।

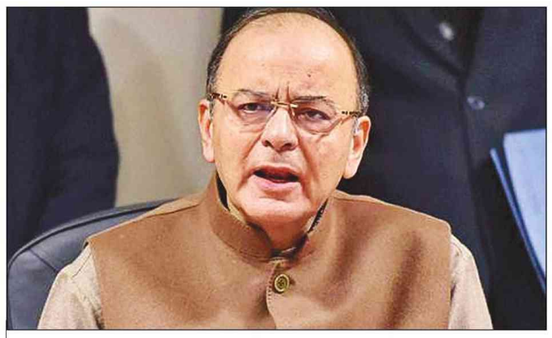

डिजिटल लेनदेन

- **25** करोड़ जनधन खातों में सीधे सरकारी सब्सिडी देना शुरू
- **1.25** करोड़ लोग भीम एप, आधार पे और यूपीआई से
- **2025** तक नकद लेनदेन को 50% तक लाने का लक्ष्य
- **02** लाख रुपये से अधिक का नकद लेनदेन गैरकानूनी

कृषि क्षेत्र

- **2.69** करोड़ किसान फसल बीमा योजनाओं के दायरे में 2016 तक
- **06** करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे मार्च 2017 तक
- **10** फीसदी यूरिया की खपत कम हुई नीम लेपित यूरिया के निर्णय से
- **20** लाख टन का बफर स्टॉक दालों का, किसानों को सही दाम मिले

केंद्र के तीन अहम बदलाव

1. केंद्र सरकार ने कालाबाजारी खत्म करने के लिए 64 विभागों की 533 योजनाओं को नकद सब्सिडी हस्तांतरण में लाने का फैसला किया है।
2. सरकार ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव कर बैंकों के कर्ज की वसूली और निपटारे के मामले में रिजर्व बैंक को अधिकार दिए हैं। देश में बैंकों का करीब आठ लाख करोड़ का कर्ज फंसा है।
3. बेनामी संपत्ति संशोधित कानून 1 नवंबर 2016 से लागू हुआ। इसमें बेनामी संपतियों को जब्त करने, जुर्माने के साथ 7 साल कैद का भी प्रावधान है।

अर्थव्यवस्था

नोटबंदी व जीएसटी जैसे कदम अहम साबित होंगे

फैसला : नवंबर 2016 में सरकार ने हजार और पांच सौ के नोट बंद करने का फैसला लिया। वहीं जीएसटी एक जुलाई से लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। जीएसटी परिषद ने 500 सेवाओं और 1200 से ज्यादा वस्तुओं की कर की दरें तय कर दी है। सरकार को उम्मीद है कि इससे महंगाई दो फीसदी कम होगी।

हकीकत : नोटबंदी से आर्थिक विकास पर भले ही फर्क न दिखा हो, लेकिन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की हालत बिगड़ी है। बैंकों का एनपीए एक लाख करोड़ रुपये बढ़ा है और बड़े कर्जदारों से कर्ज वसूली नहीं हो पाई है।

सवाल : आर्थिक विकास के साथ रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। देश में हर साल करीब एक करोड़ युवा पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं। हर साल एक से दो करोड़ रोजगार का वादा फिलहाल हकीकत से दूर नजर आ रहा है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था

कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने पर पूरी ताकत झोंकी

फैसला : काले धन और भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए सरकार ने डिजिटल लेनदेन पर पूरी ताकत झोंकी। आधार नंबर के जरिये भुगतान, भीम एप, यूपीआई और यूएसएसडी इसी का उदाहरण है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर सार्वजनिक मंच पर इसकी वकालत की। 14 से ज्यादा योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में डाला जाएगा।

हकीकत : आठ नवंबर को नोटबंदी के बाद भारी डिजिटल लेनदेन के दो-तीन माह के भीतर ही नोटों का चलन फिर बढ़ने लगा। जोखिम, समझ और जागरूकता की कमी से गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की हिचक कायम है।

सवाल : रैनसमवेयर जैसे बड़े साइबर हमले, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड का डाटा लीक होने जैसी घटनाएं डिजिटल लेनदेन के लिए चुनौती हैं। लचर साइबर कानूनों के साथ साइबर अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञ पुलिसबल और जांचकर्ताओं की भारी कमी है।

कृषि क्षेत्र

खाद्यान्न के दाम काबू करने में कामयाबी मिली

फैसला : मोदी सरकार पहले दो साल भयंकर सूखे को देखते 2016 में महज दो फीसदी प्रीमियम पर फसल बीमा योजना लाई। नीम लेपित यूरिया के अलावा मिट्टी के अनुरूप खाद के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड योजना को किसानों ने हाथोंहाथ लिया है। फसल का उचित दाम दिलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार तैयार किया जा रहा है।

हकीकत : कृषि ऋण न लेने वाले किसानों को फसल बीमा के दायरे में लाने में मामूली वृद्धि हुई है। यह 2015 में 98.4 लाख से 2016 में 1.01 करोड़ तक ही पहुंचा। बंपर पैदावार से किसानों को अरहर का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है।

सवाल : 2019-20 तक 50 फीसदी किसानों को फसल बीमा के तहत लाने के लक्ष्य से सरकार कोसों दूर है। किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला भी नहीं रुक रहा है। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है।

सुधारवादी सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं, वित्तीय नियमों, योजना-गैर योजनागत खर्च के वर्गीकरण का खात्मा, कर व्यवस्था में सुधार, बजट परिणामों पर जोर दिया है। कैबिनेट से सचिव स्तर तक 300 से 35 करोड़ के खर्च की मंजूरी का अधिकार दिया है। -**रवि सिंह,** आर्थिक विशेषज्ञ

मोदी सरकार के सामने दो साल में जीएसटी को समुचित तरीके से लागू कराने की चुनौती है। सरकार बैंकों का कर्ज लेकर विदेश भाग चुके अपराधियों के खिलाफ कानून लाने वाली है। काले धन और बेनामी संपत्ति के कानूनों का असर दिखना अभी बाकी है। -**वेद जैन,** आर्थिक विशेषज्ञ